मंगलम् ग्रुप ने 100 बीघा कृषि भूमि पर बसा दी अवैध कॉलोनी 'फोरेस्टा'

दिल्ली बाईपास रोड पर ग्राम टोडी से दौलतपुरा के बीच में काटी अवैध कॉलोनी

- मंगलम ग्रुप ने ना तो कृषि भूमि का कोई रूपांतरण कराया और ना ही जेडीए प्रशासन से कोई निर्माण स्वीकृति ली
- जे.डी.ए. की प्रवर्तन टीम ने रातोंरात बनाई गई मिट्टी-ग्रेवल रोड, बाउंड्रीवाल समेत अन्य अवैध निर्माण ध्वस्त किए

जयपुर (कासं)। राजधानी जयपुर में दिल्ली बाईपास रोड स्थित ग्राम टोडी से दौलतपुरा के बीच 100 बीघा कृषि भूमि पर मंगलम ग्रुप ने अवैध कॉलोनी ''फोरेस्टा'' बसा दी। इसके लिए जयपुर विकास प्राधिकरण से ना तो कोई परमिशन ली गई और ना ही भू-रूपांतरण कराया। भूमाफियाओं की तरह रातोंरात ही यह कॉलोनी काटकर इसमें मिट्टी-ग्रेवल व डामर की सड़कें, बाउंड्रीवाल समेत कई निर्माण कर दिए। सोमवार को जेडीए के मुख्य नियंत्रक प्रवर्तन महेन्द्र कुमार शर्मा की टीम ने इस अवैध कॉलोनी पर कार्रवाई करते हुए तमाम अवैध निर्माण जेसीबी मशीनों की मदद से ध्वस्त किए।

मुख्य नियंत्रक प्रवर्तन महेन्द्र कुमार शर्मा ने बताया कि जोन-13 में दिल्ली रोड बाईपास पर निजी खातेदारी की 100 बीघा कृषि भूमि पर मंगलम ग्रुप द्वारा अवैध कॉलोनी 'फोरेस्टा' बसाने की जानकारी मिली। जब संबंधित जोन उपायुक्त से इस स्कीम से जुड़ी जानकारी मांगी गई तो मालूम चला कि कृषि भूमि का ना तो आवासीय रूपांतरण (90ए) कराया गया है और ना ही कॉलोनी बसाने की कोई परमिशन जेडीए प्रशासन से ली गई है। इस पर सोमवार को जेडीए की प्रवर्तन टीम ने मौके पर कार्रवाई करते हुए तमाम अवैध निर्माणों को ध्वस्त किया। अब संबंधित जोन उपायुक्त को मंगलम ग्रुप के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए कहा गया है। इसी प्रकार जोन-13 स्थित ग्राम सेवापुरा में कचरा डिपो के पास भी करीब 27 बीघा निजी खातेदारी कृषि भूमि पर इसी तरह दूसरी अवैध कॉलोनी बसाने के लिए रातोंरात कई निर्माण कर लिए गए थे। यहां पर भी ग्रेवल व डामर की रोड, बाउंड्रीवाल व प्लॉट्स के चिन्हिकरण का काम कर लिया गया था। दोनों जगहों पर ध्वस्तीकरण की खर्च राशि संबंधित लोगों से वसूली जायेगी।

जयपुर विकास प्राधिकरण की प्रवर्तन टीम ने दिल्ली बाईपास रोड स्थित अवैध कॉलोनी फोरेस्टा में रातोंरात बनाई गई डामर सड़क व अन्य निर्माण ध्वस्त किए।

मानसरोवर में राधा गोविंद जूस सेंटर पर खाद्य सुरक्षा टीम ने छापेमारी की

यहां पर जूस में हानिकारक रंग और पाम आयल का फ्रोजन डेजर्ट मिलाकर लोगों को पिलाया जा रहा था

जयपुर । मानसरोवर स्थित प्रतिष्ठित राधा गोविंद जूस सेंटर पर सोमवार को चिकित्सा विभाग की खाद्य सुरक्षा टीम ने छापेमारी की। यहां पर जूस में हानिकारक रंग और पाम आयल का फ्रोजन डेजर्ट मिलाकर लोगों को पिलाया जा रहा था।

अतिरिक्त आयुक्त पंकज ओझा ने बताया कि यहां फलों के भंडारगृह में और फ्रीज में भारी मात्रा में गंदगी पाई गई। फ्रोजन डेजर्ट और रंग डालकर जूस बनाए जा रहे थे। ताजे फलों से जूस बनाने के बजाय फलों को कई दिन पूर्व ही काटकर फ्रीज़ों में भर रखा गया था। साथ ही हानिकारक रंग और पाम आयल का फ्रोजन डेजर्ट मिलाया जा रहा था। डीप फ्रीजर में कई दिन पुराने कटे फल मिले जिन पर कोई टैगिंग नहीं थी। डीप फ्रीज़र में काली फंगस लगी हुई थी और साथ ही, गोदाम में सड़े हुए फल, चासनी, खुले में रखी चीनी, गंदी दीवारें, जंग लगी अलमारियां मिली यहां से मीडियम फैट फ्रोजन डेजर्ट , कीवी शेक, पपीता शेक का नमूना लिया गया, जिन्हें जांच हेतु प्रयोगशाला भिजवाया गया है। जांच रिपोर्ट प्राप्त होने के पश्चात खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 नियम एवं विनियम 2011 के अनुसार अग्रिम कार्रवाई की जाएगी।

फर्म के भंडार गृहों में अत्यधिक गंदगी मिलने और फूड एटीकैट्स की अवहेलना के कारण एफएसएसए की धारा 32 के तहत इंप्रूवमेंट नोटिस दिया जाएगा। इस कार्रवाई में मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जयपुर द्वितीय के खाद्य सुरक्षा अधिकारी दीपक कुमार सिंधी, राजेश कुमार नागर और नंदकिशोर कुमावत शामिल रहे। ज्ञात रहे कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की पहल एवं चिकित्सा मंत्री गजेन्द्र सिंह खींवसर के निर्देश पर प्रदेश में ''शुद्ध आहार-मिलावट पर वार'' अभियान निरंतर जारी है। इसी कड़ी में खाद्य सुरक्षा आयुक्त इकबाल खान के निर्देशन में सोमवार को मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जयपुर द्वितीय के खाद्य सुरक्षा अधिकारियों की टीम ने इस छापेमारी को अंजाम दिया।

अविचल चतुर्वेदी ने किया बच्चों से संवाद

जयपुर । राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद् के राज्य परियोजना निदेशक अविचल चतुर्वेदी ने राजकीय उच्च प्रथमिक विद्यालय करतारपुरा और राजकीय उच्च प्रथमिक विद्यालय बम्बाला (सांगानेर) में पहुंचकर प्रखर राजस्थान अभियान के शुभारम्भ अवसर पर आयोजित रीड ए थॉन गतिविधि में सम्मिलित हुए। उन्होंने विद्यार्थियों से संवाद किया तथा विद्यालय में अध्यननरत विशेष आवश्यकता वाली बालिका से लार्ज फोंट पुस्तिका पढवाकर बालिका का उत्साहवर्द्धन किया। चतुर्वेदी ने अजमेर के राजकीय अंध विद्यालय, आदर्श नगर के बालकों से वीडियो कॉल पर जुड़कर ब्रेल पुस्तक वाचन की प्रशंसा की। कलेक्टर भी प्रखर राजस्थान अभियान में सहभागी बने। जिला कलेक्टर-बांसवाड़ा डॉ. इन्द्रजीत सिंह ने पीएमश्री महात्मा गांधी विद्यालय, खांदू कॉलोनी, कलेक्टर-बीकानेर नम्रता वृष्णि ने राजकीय अंध विद्यालय बीकानेर, कलेक्टर-भीलवाड़ा नमित मेहता, महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय, पुलिस लाइन, भीलवाड़ा में पहुंचकर विद्यार्थियों से संवाद कर अभियान को उत्साहपूर्वक संचालित करने के लिए प्रेरित किया।

अतिरिक्त राज्य परियोजना निदेशक सुरेश कुमार बुनकर अभियान के दौरान राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय शुभरामपुरा, जयपुर में पहुंचकर विशेष आवश्यकता वाले बालक से संवाद कर उत्साहवर्द्धन किया। राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद के अधिकारियों द्वारा भी अपने-अपने प्रभार वाले जिलों में पहुंचकर कार्यक्रम में सहभागिता की।

राज्य सूचना आयोग ने जे.डी.ए. जोन 6 उपायुक्त पर 15 हजार रु. जुर्माना लगाया

- सूचना नहीं देने पर 15 हजार रु. की क्षतिपूर्ति राशि भी परिवादी को देने के आदेश भी दिए

जयपुर । राजस्थान सूचना आयोग ने राज्य लोक सूचना अधिकारी एवं जे.डी.ए. उपायुक्त जोन-6 द्वारा सूचना उपलब्ध नहीं करवाने और राजस्थान सूचना आयोग के निर्णय की पालना नहीं करने पर उपायुक्त पर 15000 हजार रु. का जुर्माना और 15 हजार रु. क्षतिपूर्ति अधिरोपित करने का निर्णय दिया है। यह निर्णय परिवादी मुरलीपुरा स्कीम निवासी असीम मालावत के तीन अलग-अलग परिवार पर दिया गया है।

परिवादी की ओर से एडवोकेट भगवत गौड़ ने राज्य सूचना आयोग में पैरवी करते हुये उपायुक्त द्वारा सूचना उपलब्ध नहीं करवाने को अधिनियम की जानबूझकर कर अवहेलना करना बताया। एडवोकेट गौड़ ने बताया कि परिवादी द्वारा अक्टूबर 2021 में तीन अलग अलग आवेदन प्रताप कर सूचना चाही थी, जिनकी सूचना उपायुक्त जोन-6 ने उपलब्ध नहीं करवायी थी। इस पर राजस्थान सूचना आयोग में तीन द्वितीय अपील प्रस्तुत की गयी थी, जिनका निर्णय सूचना आयोग ने फरवरी 2023 में करते हुये उपायुक्त जोन- 6 को सूचना उपलब्ध करवाने बाबत आदेश दिया था। उपायुक्त जोन-6 ने आयोग के द्वितीय अपील के निर्णय की पालना नहीं करने पर परिवादी असीम मालावत ने सूचना आयोग में तीन परिवाद प्रस्तुत किये जिनका निर्णय करते हुये मुख्य सूचना आयुक्त मोहन लाल लाठर ने उपायुक्त के कृत्य को सूचना का अधिकार अधिनियम की घोर उपेक्षा मानते हुये प्रत्येक परिवाद में पांच हजार रूपये जुर्माना आयोग में जमा करवाने और पांच हजार रूपये क्षितपूर्ति राशि परिवादी को अदा करने का निर्णय दिया है।

इस प्रकार उपायुक्त जोन-6 को तीन परिवाद पर जुर्माना राशि पन्द्रह हजार रूपये आयोग में जमा करवाने होंगे और पन्द्रह हजार रूपये परिवादी असीम मालावत को देनी होगी। एडवोकेट भगवत गौङ ने बताया कि जुर्माना राशि और क्षितपूर्ति राशि उपायुक्त जोन-6 के वेतन से काटने का आयोग ने आदेश दिया है और आयुक्त जयपुर विकास प्राधिकरण को निर्णय की प्रति भेजते हुये उपायुक्त जोन-6 के खिलाफ विभागीय कार्रवाई करते हुये सर्विस बुक में अंकन करने का भी आदेश दिया है।

सार-समाचार

'नि-क्षय मित्र बनाएं-टीबी हराएं' अभियान

जयपुर । प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान की द्वितीय वर्षगांठ के अवसर पर सोमवार को चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग की ओर से 'नि-क्षय मित्र बनाएं-टीबी हराएं' अभियान शुरू किया गया। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग की प्रमुख शासन सचिव गायत्री राठौड़ ने शासन सचिवालय स्थित अपने कक्ष में पोस्टर का विमोचन कर अभियान की शुरूआत की। यह अभियान 9 सितम्बर से 2 अक्टूबर तक संचालित किया जाएगा। राठौड़ ने इस अवसर पर कहा कि राज्य सरकार प्रदेशवासियों को बेहतर चिकित्सा सेवाएं उपलब्ध करवाने के लिए प्रतिबद्ध है। चिकित्सा मंत्री गजेन्द्र सिंह खींवसर के मार्गदर्शन में प्रदेश को टीबी मुक्त बनाने की दिशा में विभाग निरंतर जरूरी कदम उठा रहा है। उन्होंने कहा कि ब्लॉकवार नि-क्षय मित्र बनाने का लक्ष्य निर्धारित कर नियमित समीक्षा की जाए। अधिकाधिक जनभागीदारी सुनिश्चित कर टीबी के प्रति जागरूकता फैलाएं और इस अभियान को सफल बनाएं। उल्लेखनीय है कि 9 सितम्बर को 'प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान' का शुभारम्भ किया गया था।

कवि सम्मेलन का आयोजन

जयपुर । ''हर परिंदे को खुले आसमान का हक है'' इसी भावना के साथ जयपुर टोंक रोड स्थित एक होटल में कवि सम्मेलन आयोजित किया गया। पार्षद गोविंद छीपा ने बताया कि प्रतिवर्ष सितंबर माह के दूसरे रविवार को बर्ड फ्रीडम डे नामक संस्था इस तरह के आयोजन करती है। इस कार्यक्रम का मुख्य आकर्षण महाभारत सीरियल में अर्जुन का किरदार निभा चुके फिरोज़ खान थे। शाम से ही रसिक श्रोता जुटने लगे थे जो रात 10 बजे तक कविताओं का आनंद लेते रहे। मुख्य आयोजक विपिन कुमार जैन ने बताया कि कार्यक्रम में महापौर डॉ सौम्या गुर्जर, समाज सेवी श्रवण बगड़ी सहित अनेक गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे। किशोर पारीक, वरुण चतुर्वेदी, संतोष चारण आदि 11 कवियों ने अपनी रचनाएं प्रस्तुत की।

बंधन बैंक देगा जीएसटी कलेक्शन सुविधा

जयपुर । बंधन बंक ने अब जीएसटी (वस्तु और सेवा कर) कलेक्शन की सुविधा शुरू कर दी है। अब बैंक के कस्टमर्स और नॉन-कस्टमर्स दोनों ही ऑनलाइन और ऑफलाइन तरीके से जीएसटी भर सकते हैं। इससे जीएसटी का पेमेंट करना काफी आसान हो गया है। बैंक के कस्टमर्स और अन्य लोग अब बैंक के रिटेल इंटरनेट बैंकिंग और कॉर्पोरेट इंटरनेट बैंकिंग प्लेटफॉर्म के जरिए जीएसटी पेमेंट कर सकते हैं। इसके अलावा, बैंक की किसी भी शाखा में जाकर कैश, चेक या डिमांड ड्राफ्ट से भी पेमेंट किया जा सकता है। बंधन बैंक के कार्यकारी निदेशक और मुख्य व्यवसाय अधिकारी, राजिंदर बब्बर ने कहा, ''जीएसटी कलेक्शन की शुरुआत हमारे ग्राहकों के लिए सरकारी सेवाओं को और भी नजदीक लाने की दिशा में एक अहम् कदम है। सरकार जब व्यापार को आसान बनाने पर ध्यान दे रही है, बंधन बैंक अपनी बेहतरीन डिजिटल और तकनीकी क्षमताओं से सकारात्मक बदलाव लाने के लिए प्रतिबद्ध है।'' बंधन बैंक अब 36 में से 35 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में मौजूद है, और पूरे भारत में 6300 से ज्यादा बैंकिंग आउटलेट्स के मजबूत नेटवर्क से 3.44 करोड़ से ज्यादा कस्टमर्स को सेवाएँ दे रहा है।

नीमराणा फायरिंग मामले की शिकायत

जयपुर । अलवर जिले के नीमराणा में बदमाशों द्वारा दिनदहाड़े 32 राउंड फायरिंग करते हुए 5 करोड़ रु. की फिरौती की पर्ची थमाने के मामले की शिकायत प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सचिव गिरिराज खंडेलवाल ने गृह विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव आनंद कुमार को दी है। उन्होंने कहा कि होटल हाइवे किंग पर बदमाशों ने पांच करोड़ रुपये वसूली की धमकी देते हुए बेतहाशा गोलियां चलायी। इसके बाद बेखौफ होकर फरार हो गये। यह घटना प्रदेश के आम नागरिकों व उद्योगपतियों में भय का माहौल पैदा कर रही है। चूंकि नीमराणा विश्व विख्यात औद्योगिक नगरी हैं, ऐसे में अगर यहां अपराधी इतने बेखौफ होंगे तो विदेशी कंपनियां यहां निवेश से कतराएंगी।

हज के आवेदन 11 से 30 सितंबर तक

जयपुर । राजस्थान हज कमेटी के पास अब तक 2000 भी आवेदन नहीं मिले हैं। हज 2025 के लिये सेंट्रल हज कमेटी मुम्बई के द्वारा हज आवेदन की तारीख 13 अगस्त से 9 सितंबर रखी गई थी, परंतु हज कमेटी की गाईड लाईन 2025 की वजह से हज यात्री हज कमेटी से फार्म भरने में काफी सोच विचार कर रहे हैं। राजस्थान स्टेट हज कमेटी के सदस्य हाजी शाहिद मौहम्मद ने बताया कि सेंट्रल हज कमेटी की गाईड लाईन के अनुसार अबकी बार हज यात्रियों को मक्का-मदीना में महिलाओं ओर पुरुषों को अलग-अलग रखे जाने और मक्का में किचन की सुविधा बंद करने का भी मुख्य कारण है। रिजर्व केटेगरी के हज यात्रियों के साथ जो केम्पेनियन का आवदेन करने में भी कठिनाई है।

महेन्द्र सोनी ने ली बैठक

महिला एवं बाल विकास विभाग के शासन सचिव महेन्द्र सोनी की अध्यक्षता में सोमवार को विभागीय समीक्षा बैठक आयोजित हुई।

जयपुर । शासन सचिव महिला एवं बाल विकास महेन्द्र सोनी ने राष्ट्रीय पोषण माह में बेहतर प्रदर्शन करने के अधिकारियों को निर्देश दिए गए। उन्होंने मुख्य प्रदर्शन संकेतक (केपीआई) में राज्य स्तर पर निम्न प्रदर्शन करने वाले जिलों को प्रदर्शन सुधारने के निर्देश दिए।

शासन सचिव महिला एवं बाल विकास महेन्द्र सोनी की अध्यक्षता में सोमवार को निदेशालय समेकित बाल विकास सेवाएं, जयपुर (आईसीडीएस मुख्यालय) में विभागीय समीक्षा बैठक आयोजित की गई। शासन सचिव को आईसीडीएस निदेशक ओपी बुनकर ने विभागीय गतिविधियों एवं योजनाओं की बिंदुवार विस्तार से जानकारी दी।

शासन सचिव सोनी को निदेशक बुनकर ने राज्य में चल रहे राष्ट्रीय पोषण माह के अंतर्गत आयोजित हो रही गतिविधियों की जानकारी दी। उन्होंने राज्य के राष्ट्रीय स्तर पर प्रदर्शन की भी जानकारी दी। शासन सचिव को विभाग के संरचनात्मक ढांचे, रिक्त पदों और विभागीय डीपीसी के सम्बन्ध में विस्तार से जानकारी दी गई। विभाग रिक्त के पदों पर भर्ती करने के लिए राजस्थान लोक सेवा आयोग को भेजे जाने वाली अभ्यर्थना की भी शासन सचिव को जानकारी दी गई। बैठक में अतिरिक्त निदेशक चान्दमल वर्मा, अतिरिक्त निदेशक मेघराज सिंह मीना, अतिरिक्त निदेशक संजय शर्मा, संयुक्त परियोजना समन्वयक डॉ. मंजु यादव और अन्य विभागीय अधिकारी उपस्थित रहें।

एस.बी.आई. जयपुर मंडल ने किया पौधारोपण

जयपुर । भारतीय स्टेट बैंक (एस.बी.आई.) जयपुर मण्डल की ओर से 5 सितम्बर को अमृतादेवी पर्यावरण नागरिक (अपना) संस्थान जयपुर के माध्यम से राजकीय कन्या उच्च माध्यमिक विद्यालय, कंवर नगर, जयपुर में वृक्षारोपण किया गया। कार्यक्रम में भारतीय स्टेट बैंक के स्वतंत्र निदेशक धर्मेंद्र सिंह शेखावत, महाप्रबंधक ऋतु गौड़, बैंक के उप महाप्रबंधक, सहायक महाप्रबंधक एवं अन्य अधिकारी मौजूद रहे।

स्वतंत्र निदेशक शेखावत ने कहा कि केवल ''प्लान्ट फॉर मदर'' ही काफी नहीं है, बल्कि ''प्लान्ट फॉर एवरी फ़ैमिली मैंबर'' के ध्येय को अपनाना होगा। ज्यादा से ज्यादा ऐसे पेड़ लगाने होंगे, जिनकी चिकित्सयी उपयोगिता हो जैसे कि कदंब, पीपल, बड़, नीम इत्यादि।

उन्होने एसबीआई द्वारा बैंक के सीएसआर कार्यक्रम के अंतर्गत ग्रेटर नगर निगम एरिया में 15 हजार वृक्ष लगाने के इस प्रयास का भी विशेष उल्लेख किया। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की महाप्रबंधक गौड़ ने मानव के लिए वृक्षों का महत्व बताया।

आई.ए.एस. श्रुति भारद्वाज ने किया जयपुर डेयरी प्लान्ट का निरीक्षण

राजस्थान को-ऑपरेटिव डेयरी फैडरेशन के प्रबन्ध संचालक का पद संभालने के बाद श्रुति भारद्वाज ने जयपुर डेयरी प्लांट का औचक निरीक्ष किया। इसके बाद अधिकारियों की बैठक लेकर कई मुद्दों पर चर्चा की।

जयपुर (कासं)। भारतीय प्रशासनिक सेवा की अधिकारी श्रुति भारद्वाज ने राजस्थान को-ऑपरेटिव डेयरी फैडरेशन के प्रबन्ध संचालक पद का कार्यभार संभाल लिया है।

पदभार संभालने के बाद उन्होंने जवाहर लाल नेहरु मार्ग स्थित सरस संकुल मुख्यालय में डेयरी फैडरेशन के वरिष्ठ अधिकारियों की बैठक ली। उन्होंने डेयरी फैडरेशन और इससे सम्बद्व जिला दुग्ध संघों की आर्थिक एवं भौतिक गतिविधियों की समीक्षा की। उन्होंने फैडरेशन के वरिष्ठ अधिकारियों को सम्बोधित करते हुए कहा कि सरस ब्राण्ड के दूध और दुग्ध उत्पादों की उच्च गुणवत्ता से कोई समझौता नहीं किया जावेगा। उन्होंने राजस्थान राज्य में डेयरी विकास के क्षेत्र में निजी डेयरियों से प्रतिर्स्पधा की चुनौतियों के लिये तैयार रहने और सहकारी डेयरी की विशिष्ट पहचान बन चुके सरस ब्राण्ड को राष्ट्रीय स्तर तक पहुँचाने का आहवान किया।

इसके साथ ही, ग्लोबल मार्केट में सरस ब्राण्ड के लोंगलाईफ मिल्क प्रोडक्टस की सम्भावनाओं को तलाशने के निर्देश दिये। उन्होंने दिसम्बर माह में राज्य सरकार की प्रस्तावित इंवेस्टर्स समिट राईजिंग राजस्थान में डेयरी फैडरेशन की प्रतिभागिता की तैयारी के निर्देश भी दिये। श्रुति भारद्वाज ने आज ही जयपुर डेयरी प्लान्ट का भ्रमण किया। उन्होंने जयपुर डेयरी के नवीन डेयरी संयंत्र, पाउडर प्लान्ट, टेट्रापेक प्लान्ट, घी प्लान्ट आदि का निरीक्षण किया और जयपुर डेयरी द्वारा प्लान्ट परिसर में हाईजनिक कंडीशंस पर संतोष जाहिर किया। जयपुर डेयरी के अध्यक्ष ओम पूनिया ने उन्हें जयपुर डेयरी की आर्थिक एवं भौतिक गतिविधियों की विस्तृत जानकारी दी। इस अवसर पर फैडरेशन के वित्तीय सलाहकार ललित वर्मा और महाप्रबन्धक (परियोजना) प्रीतेश जोशी भी मौजूद रहे।

सड़क निर्माण के 15 लाख रु. के काम में ऐसी शर्त डाल दी कि सीमेंट कंपनी ही ले सके टैंडर

जे.डी.ए. जोन-7 के अधिशाषी अभियंता ने पहले सिंगल फर्म को मंजूरी दी, अब वर्क ऑर्डर देने की तैयारी

- **सूत्रों की मानें तो 15 लाख रु. के टैंडर में नियमानुसार डी श्रेणी का ठेकेदार भी भाग ले सकता है, लेकिन चहेती फर्म को काम देने के लिए इंजीनियर्स ने तकनीकी शर्त ही बदल दी**
- **इसका नतीजा यह हुआ कि टैंडर में सिर्फ उदयपुर की एक सीमेंट निर्माता कंपनी केमिको लि. ने निविदा में हिस्सा लिया, बाकी ठेकेदार इस टैंडर में भाग ही नहीं ले पाए**
- **जब ठेकेदारों ने अभियांत्रिकी निदेशक से इस मामले की शिकायत की तो उच्चाधिकारियों ने इस निविदा को निरस्त करने के निर्देश दिए, इसके बावजूद जोन-7 के अधिकारी फर्म को वर्क ऑर्डर देने की तैयारी में जुटे हैं।**

जयपुर (कासं)। जयपुर विकास प्राधिकरण के जोन-7 में अधिशाषी अभियंता ने अपने स्तर पर सीमेंट सडत्रक बनाने का काम सिंगल फर्म को दे दिया। टैंडर भरने में भी ऐसी शर्त लगा दी कि कोई दूसरी कंपनी भाग ही नहीं ले सकती। इसके बाद अब इस टैंडर को मंजूरी देकर जोन 7 के एक्सईएन तरूण सिंघल ने ठेकेदार को वर्क आर्डर देने की तैयारी कर ली है।

सूत्रों की मानें तो जेडीए जोन-7 में सीमेंट सड़क बनाने का काम होना है। इसके लिए 15 लाख का टैंडर जारी किया गया था। इस टैंडर में कुछ ऐसी तकनीकी शर्त डाल दी जो सिर्फ सीमेंट बनाने वाली कंपनी ही पूरा कर सकती है। तकनीकी शर्त होने के कारण उदयपुर की एक सीमेंट कंपनी केमको लिमिटेड ने 15 लाख का टैंडर भर दिया। स्थानीय ठेकेदारों ने इस कार्य का विरोध भी किया लेकिन अधिशाषी अभियंता तरूण सिंघल के आगे उनकी एक भी नहीं चली। इन ठेकेदारों का कहना था कि 15 लाख का टैंडर तो डी क्लास श्रेणी का ठेकेदार भी भर सकता है, ऐसे में उन्हें इस ठेके में भाग लेने से वंचित रखा गया। इस कारण ठेका निरस्त कर दुबारा निविदा जारी की जानी चाहिए। साथ ही विवादित शर्तों को भी हटाया जाना चाहिए।

सूत्रों के मुताबिक जोन-7 के इंजीनियर्स सीमेंट सड़क बनाने का यह काम अपनी चहेती फर्म केमको लिमिटेड को देना चाहते थे, चूंकि कार्य की अनुमानित लागत मात्र 15 लाख रु. ही थी। ऐसे में डी श्रेणी के ठेकेदार भी आर.टी.पी.पी. एक्ट के मुताबिक इस कार्य के लिए निविदा में भाग ले सकते थे। यह प्रतिस्पर्धा खत्म करने के लिए इस निविदा में तकनीकी शर्त बदल दी गई। सूत्रों की मानें तो टैंडर में सफल रही केमको कंपनी ने भले ही यह काम करने की सहमति दे दी हैं, लेकिन असल में वह भी इस कार्य को किसी अन्य ठेकेदार को पेटी कांटेक्ट पर देना चाहती है। सूत्रों की मानें जब इस टैंडर की शिकायत अभियांत्रिकी निदेशक तक पहुंची तो उन्होंने भी सिंगल फर्म वाले इस टैंडर को निरस्त करने के निर्देश दिए थे, लेकिन उच्चाधिकारियों के निर्देश के बावजूद भी जोन-7 के अधिशाषी अभियंता ने निविदा निरस्त नहीं की। अब इस फर्म को वर्क ऑर्डर देने की तैयारी में जुटे हैं।

मुख्यमंत्री जन आवास हो अथवा अन्य निर्माण, गुणवत्तापूर्ण कार्य होने चाहिए : वैभव गालरिया

जयपुर । नगरीय विकास विभाग के प्रमुख शासन सचिव और हाऊसिंग बोर्ड चेयरमैन वैभव गालरिया ने सोमवार को आवासन मंडल मुख्यालय में वरिष्ठ अफसरों की बैठक ली। उनके साथ आवासन आयुक्त डॉ. रश्मि शर्मा भी मौजूद रहीं। गालरिया ने कहा कि मुख्यमंत्री जन आवास योजना हो या अन्य कोई भी निर्माण, राजस्थान आवासन मंडल की प्राथमिकता गुणवत्ता होना चाहिए। उन्होंने आवासन मंडल द्वारा किए जा रहे आगामी निर्माण कार्यों और नीलामी प्रक्रिया पर चर्चा की। नीलामी और आवंटन प्रक्रिया में तेजी लाने, प्रोजेक्ट्स समय पर पूरे करने तथा भूमि अधिग्रहण संबंधी लंबित मामलों के शीघ्र निस्तारण पर जोर दिया। गालरिया ने कहा कि राजस्थान आवासन मंडल की ओर से किए जा रहे सभी कार्य चाहे वो साधारण निर्माण हों या फिर मुख्यमंत्री जन आवास योजना, सभी को समय पर पूरा करने पर फोकस किया जाना चाहिए। ऐसा भी ना हो कि तेजी के कारण गुणवत्ता को भूल जाएं।